

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्या: 10/2020

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

- (1) कालूराम पुत्र गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा, तह. व जिला-सिरोही
- (2) टीपूदेवी पत्नी गमना जी, जाति-कलबी, निवासी- सियाकरा, तह. व जिला-सिरोही
- (3) त्रिजादेवी पुत्री गमना जी, जाति-कलबी, निवासी-सियाकरा, तह. व जिला-सिरोही
- (4) तुलसी पुत्री गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा, तह. व जिला-सिरोही
- (5) धोकीदेवी पुत्री गमना जी, जाति-कलबी, निवासी- सियाकरा, तह. व जिला-सिरोही
- (6) नतूदेवी पुत्री गमना जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा, तह. व जिला-सिरोही
- (7) मकनाराम पुत्र गमना जी, जाति-कलबी, निवासी- सियाकरा, तह. व जिला-सिरोही

“प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970”

उपस्थिति:

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अप्रार्थीगण की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 104/32 रकबा 10-00 बीघा (जिसके वर्तमान खाता संख्या 94 खसरा संख्या 152 रकबा 9.1000 हेक्टेयर किस्म बंजर में अप्रार्थीगण के प्रत्येक का हिस्सा 81/3185 है) भूमि का गैर खातेदारी तौर पर गमना पुत्र मोटा जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा को आवंटन हुआ था। आवंटिती गमना की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 81/3185 दर्ज है। यह कि खसरा गिरदावरी की नकल संवत् 2061-2064 तक के अनुसार आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की है व न ही कब्जा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी/आवंटिती का संवत् 2061-2064 तक में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण/आवंटिती द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान परोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री गमना पुत्र मोटा जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा को ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 104/32 रकबा 10.00 बीघा (जिसके वर्तमान खाता संख्या 94 खसरा संख्या 152 रकबा 9.100 हेक्टेयर में

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



अप्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 81/3185 किस्म बंजर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है।) भूमि का आवंटन गैर खातेदारी तौर पर हुआ था। अप्रार्थीगण/आवंटिती का संवत् 2061-2064 तक में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं रहा है। अप्रार्थीगण/आवंटिती द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर श्री गमना पुत्र मोटा जी, जाति-कलबी, निवासी- सियाकरा को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री माथुर ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352-356 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काशत हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के खाता संख्या 94 खसरा संख्या 152 रकबा 9-1000 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 1-6200 हेक्टेयर (जिसके पुराने खसरा संख्या 104/32 रकबा 10.00 बीघा है) आई हुई है एवं इस कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 7 प्रत्येक का 81/3185 खातेदारी हक हिस्सा है। उक्त हक हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण का हक अधिकार व कब्जा काशत उनके पिता व पति गमना पुत्र मोटा जी कलबी के जरिये गत 55 वर्षों से अधिक समय से लगातार शांतिपूर्वक व बिना किसी रुकावट के चला आ रहा है, जो रकबा 1.6200 हेक्टेयर है। ग्राम पादरुखेडा में पुराने मूल खसरा संख्या 32 एक बहुत बड़े चक के रूप में राजकीय बिलानाम कृषि भूमि रही है जिसमें अलग अलग हिस्सों पर कई काशतकारों के कई वर्षों पुराने कब्जे चले आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि के मूल खसरा संख्या 32 में से रकबा 1.6200 हेक्टेयर कृषि भूमि पर भी अप्रार्थीगण के पिता व पति गमना पुत्र मोटा जी कलबी का कब्जा काशत एवं हक अधिकार पिछले कई वर्षों से लगातार रहा है, जिससे गमना पुत्र मोटा जी कलबी ने उक्त भूमि के आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के समक्ष आवेदन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, सिरौही ने सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर एवं मौके का भौतिक सत्यापन करके उक्त 10 बीघा अर्थात् 1.6200 हेक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश क्रमांक 1311 दिनांक 18.4.1975 से गमना पुत्र मोटा जी कलबी, निवासी- सियाकरा को आवंटन किया गया था एवं उक्त आवंटित कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 208 दिनांक 26.11.2001 के जरिये खसरा संख्या 104/32 रकबा 10.00 बीघा भूमि गमना पुत्र मोटा जी कलबी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की गई, जिसके वर्तमान खसरा संख्या 152 रकबा 1.6200 हेक्टेयर है। यह कि आवंटन के बाद गमना पुत्र मोटा जी कलबी ने उक्त आवंटित कृषि भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिये दिन रात मेहनत की व भूमि सुधार में काफी रकम खर्च की है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि आवंटन होने के बाद उक्त भूमि पर चारों ओर कांटो की बाड़ की है, ताकि उक्त कृषि भूमि में आवारा पशु आदि प्रवेश कर फसल को नष्ट नहीं कर सके। आवंटिती गमना पुत्र मोटा जी कलबी एवं इनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर हर वर्ष बरसाती फसल बोई जाती है, लेकिन विगत 5-6 वर्षों पूर्व अकाल होने और कोरोना जैसी माहमारी के कारण अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर फसल की बुवाई नहीं कर सके। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता व पति गमना पुत्र मोटा जी कलबी अपने जीवनकाल में काबिज काशत रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण काबिज काशत चले आ रहे हैं और आवंटित कृषि भूमि में बरसाती फसल हर वर्ष बोई जाती है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा केवल उक्त चार वर्षों की खसरा गिरदावरी ही प्रस्तुत की गई है, लेकिन बरसाती फसलों का अंकन पटवारी द्वारा नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा हर वर्ष फसल बोई जाती है। उक्त भूमि आवंटन के बाद आवंटिती गमना पुत्र मोटा जी कलबी और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के सभी नियमों का पालना किया है। अप्रार्थीगण ने किसी भी नियम का नहीं किया है।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



उक्त नियमों के नियम 14(4)के अनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत व द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण कृषि भूमि पर फसल की बुवाई व जुताई की गई है। मौके पर अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर लगातार एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। यदि खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज नहीं किया गया है तो इस हेतु अप्रार्थीगण दोषी नहीं है। खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज करने का दायित्व संबंधित पटवारी का है। जबकि विधि अनुसार अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक बन चुके हैं एवं उसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अंकन किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि के लिये गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित नहीं होने से अप्रार्थीगण के उक्त कृषि भूमि के खातेदारी हक अधिकारों के प्रति शंका उत्पन्न होती है। अप्रार्थीगण उनके नाम से उक्त भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं एवं राजस्व अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि निश्चित समयावधि गुजरने के बाद उक्त कृषि भूमि की श्रेणी गैर खातेदारी से खातेदारी में अप्रार्थीगण के पिता/पति गमना पुत्र मोटा जी कलबी एवं इनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित करते, लेकिन अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों ने ऐसा नहीं कर अप्रार्थीगण के साथ कुठाराघात किया है। यह कि उक्त कृषि भूमि का अप्रार्थीगण के पिता/पति गमना पुत्र मोटा जी कलबी को आवंटन होने से इतनी लम्बी समयावधि गुजर जाने के बाद भी राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण ने उक्त आवंटन नियमों के सभी नियमों व शर्तों का पालन किया है। उक्त आवंटन नियमों के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र तब ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जब भूमि का आवंटन कपटपूर्वक या दुर्व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया हो या नियमों के विरुद्ध आवंटन किया हो या आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। जबकि उक्त कृषि भूमि का आवंटन न तो विधि विरुद्ध तरीके से हुआ है और न ही कोई आवंटन की शर्त भंग हुई है। यह कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(1) के अनुसार आवंटिती को आवंटित भूमि पर 10 वर्षों के बाद खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते हैं। अप्रार्थीगण और उनके पिता/पति गमना पुत्र मोटा जी कलबी ने उक्त आवंटित कब्जे-काश्त की भूमि पर मेहनत कर एवं काफी रकम खर्च कर उपजाऊ बनाया है। अप्रार्थीगण भूमिहीन व्यक्ति हैं एवं उक्त आवंटित भूमि पर काश्त कर अपना भरण पोषण करते हैं। विधि अनुसार आवंटन के 10 वर्षों बाद उक्त आवंटित भूमि के अप्रार्थीगण खातेदार कृषक हो चुके हैं। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरौही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सिरौही के आदेश दिनांक 18.4.1975 के द्वारा ग्राम पादरुखेडा के पुराने खसरा संख्या 104/32 रकबा 10.00 बीघा भूमि का श्री गमना पुत्र मोटा जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त श्री गमना पुत्र मोटा जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा को ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 104/32 रकबा 10.00 बीघा आवंटित भूमि, नामान्तरकरण संख्या 208 दिनांक 26.11.2001 से श्री गमना पुत्र मोटा जी, जाति-कलबी, निवासी- सियाकरा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का, सनपुर की मौका फर्द दिनांक 10.8.2020 के अनुसार आवंटित भूमि पर बबूल खड़े हैं, जहाँ पर खेती किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2061 से 2064, 2063 से 2066 व 2071-2074 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि के मौके पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा-काश्त नहीं रहा है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से भी जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा-काश्त होने के संबंध में खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नहीं की गई हैं, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा-काश्त रहा हो। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी तहसीलदार, सिरौही की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही कब्जा है तथा न ही अप्रार्थीगण ने इस संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो अप्रार्थीगण के कब्जे-काश्त का समर्थन करते हो। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरौही का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराने खसरा संख्या 104/32 रकबा 10.00 बीघा (जिसके वर्तमान खाता संख्या 94 खसरा संख्या 152 रकबा 9.1000 हेक्टेयर किस्म बंजर में प्रत्येक अप्रार्थीगण का हिस्सा 81/3185 दर्ज है) भूमि का श्री गमना पुत्र मोटा जी, जाति- कलबी, निवासी- सियाकरा को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरौही